[Dr. V. K. R. V. Rao]

from the date of expiry of his earned leave. The Visitor has accepted his resignation and directed that it should take effect from the date on which his earned leave expires.

As for the long term recommendations made by the Committee, these are of a very comprehensive and far-reaching character and would require consideration in depth and detail. As many of these long-term recommendations are also pertinent to Central Universities in general, they would require consultation with the University Grants Commission and the authorities of the different Central Universities. Government does not, therefore, propose to take any decisions on these recommendations at present, but will do so after this detailed examination and discussion has been completed.

I would like to conclude with the hope that normalcy will be restored on the campus of the University by the immediate measures that are proposed to be taken now and that its smooth and efficient functioning as an Academic Body will become a reality. May I appeal to all concerned, students, teachers, leaders of political parties and all others interested in the future of the Banaras Hindu University to extend their cooperation in seeing that one of our greatest national heritages begins to function in a manner worthy of the vision that lay behind its establishment.

श्री रवि राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्यार्थी निकाल दिए गये हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जिन विद्यार्थियों को निकाल दिया गया है, रेस्टीकेट किया गया है, उनको वापस लेना चाहिए। जब तक उन विद्यार्थियों को नहीं लिया जाएगा, तब तक शान्ति कैसे प्रस्थापित होगी ?... (**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY-SPEAKER: In the light of the findings of the...

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, बहुत से लोगों ने, संसद सदस्यों ने दस्तख्त कर के मैमोरेण्डम दिया है,... (**व्यवधान**)...यह बहुत अच्छा हुआ है कि वे जा रहे हैं, लेकिन जो कुकर्म करके जा रहे हैं... (**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will the leader of his group ask him to sit down ?

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): It is an urgent problem.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me make an observation. In the light of the findings of the committee if it is found...(*Interruptions*) I want to bring this to the notice of the hon. Minister. There is a demand for the release of the students and reconsideration of the action taken against them. The hon. Minister may examine the cases. That is all that I would like to say. Beyond that, I do not want to say anything now.

DR. V. K. R. V. RAO: The report of the Committee has now been printed and a copy is available to each member. Let them read the report and see what the committee has to say about the students on whose behalf my hon. friends are speaking.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing from 4th August, 1969, will consist of :—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Consideration of Statutory Resolution by Shri Kanwar Lal Gupta and others regarding disapproval of the Gold (Control) Amendment Ordinance, 1969 and consideration and passing of the Gold (Control) Amendment Bill, 1969.

(3) Further consideration of motion for modification of All-India services (Conduct) Rules, 1968, moved by Shri N. K. P. Salve on the 16th May, 1969.

(4) Further clause-by-clause consideration of the Criminal and Election

Laws Amendment Bill, 1968, as reported by the Joint Committee.

(5) Consideration and passing of :—

The Delhi High Court (Amendment) Bill, 1968.

The Lokpal and Lokayuktas Bill, 1968, as reported by the Joint Committee.

The Indian Registration (Amendment) Bill, 1968, as passed by Rajya Sabha.

The Oath Bill, 1968, as passed by Rajya Sabha.

(6) Discussion on the Report of the Committee on Defections on a motion to be moved by the Minister of Home Affairs.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kandrapara): On which specific date will the last item be taken up ?

SHRI RAGHU RAMAIAH: These are the items which will be taken up during next week, but this is not necessarily the order in which they will be taken up.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will decide.

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad): From the last session, I have been trying to raise a discussion on the Prime Minister's statement regarding Telengana. It was discussed in the Business Advisory Committee and it was agreed to have some time for it. But for lack of time, it could not be taken up last session.

Before this session started, I gave notice of a $2\frac{1}{2}$ hour discussion under rule 193. I have no communication from the secretariat about that. Telengana is on fire. There is almost police raj there. All the schools and colleges are closed. Thousands of CRP men are stationed there. I request you to give a direciton to find some time for this discussion.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खमम्म) : कल अमरीका के प्रेसिडेण्ट श्री निक्सन भारत आये थे, उनसे हमारी प्रधान मंत्री की बातचीत हुई है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके सम्बन्ध में क्या प्रधान मंत्री जी कोई वक्तव्य देंगी ? यदि देंगी तो कब तक ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे एक बात अर्ज करनी है। हमारे यहां इस वक्त डेढ़ लाख ट्रैक्टर्ज़ की जरूरत है, ढाई-तीन लाख के करीब किसान इस वक्त वेटिंग लिस्ट पर हैं। यह सारे देश की पीजेण्ट्री के लिए एक बहुत अहम सवाल है। 6 हजार का ट्रैक्टर इस वक्त 20 हजार में मिलता है। क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई प्रपोजल आयेगी कि वह ट्रैक्टरों को बनाने के लिए कोई फैक्टरी सैट-अप कर रहे हैं। 12 हज़ार ट्रैक्टर बनाने की इस वक्त कैपेसिटी है, जब कि डिमाण्ड डेढ़ लाख की है। इस को आप किस तरह से पूरा करेंगे ? मैं चाहता हूं कि फ़ूड मिनिस्टर साहब की तरफ़ से इस के बारे में कोई बयान आये।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण घटनायें हो रही हैं, जिन से हिन्दुस्तान का बहुत नज़दीक का सम्बन्ध है— जैसे ब्रेज़नेव साहब ने सामूहिक सुरक्षा के बारे में भाषण दिया था, अभी निक्सन साहब से प्रधान मंत्री जी की बातचीत हुई है। पचासों ऐसे मामले है—नेपाल-भारत का मामला है, चीन और रूस के संघर्ष का मामला है, भारत-पाकिस्तान का मामला है, भारत-चीन का मामला है।

इसलिए मेरी विनती है कि अगले सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करने के लिए मौका दिया जाये।

13 hrs.

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह जो सैलरीज़ बिल है, उसके बारे में घोर मतभेद है लेकिन कम से कम इसके बारे में सभी लोगों में एक राय हो गई है कि इसको तत्काल बहस के

[श्री मधु लिमये]

लिए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल हम राष्ट्रीयकरण और समाजवाद पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए अभी उसको मुल्तवी रखा जाये—यह मेरी प्रार्थना है—और जो सामाजिक लेजिस्लेशन है जैसे कि फारन मैरिजेज बिल, उसको पहले प्राथमिकता दी जाये। यही मुझे कहना था।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I fully support Shri Mirza that there should be a discussion on the Telengana situation. All the colleges and schools have been converted into jails, I am told. The students are not going there. The Bill on Members Salaries can be postponed and it should be circulated for eliciting public opinion because public opinion is against that Bill. 34 Members of Parliament had written to the Prime Minister asking her to reinstate the employees who had been suspended on 19 September last year. An amnesty should be granted and they should be taken and the recognition should be restored to the union. I have tabled call attention notices about four Ordinance factories but you in your wisdom had disallowed them. They are suffering from inadequate work load. Statements should be made by the hon. Minister that they are not retrenching... (*Interruptions*.) The workers should not suffer in the hands of the private sector.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में एक चर्चा आधी की गई थी जो कि इस अधिवेशन में पूरी होनी है। देश के विभिन्न राज्यों में जो हिंसात्मक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, कुछ राजनीतिक दलों का जिनके पीछे हाथ है और कुछ विदेशों का भी जिनके पीछे हाथ है—उसके सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था कि इस अधिवेशन में चर्चा पूरी होगी। मैं यह चाहता था कि संसद कार्य मंत्री उस विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी कार्यसूची में अवश्य रख लेते। किसी कारणवश यदि अगले सप्ताह में नहीं रख सकते तो उसके अगले सप्ताह में निश्चित रूप से उसको रख लिया जाये।

पिछले शुक्रवार को मैंने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया था कि भारत के राजनीतिक चुनावों में जो विदेशी धन का उपयोग हो रहा है, जिसको स्वयं सरकार स्वीकार कर चुकी है और इतने गम्भीर मामले पर चर्चा के लिए 'नो डे यट नेम्ड' मोशन भी स्वीकार हो गया है तो किसी न किसी समय चर्चा के लिए इसको अवश्य रखा जाये।

DR. KARNI SINGH (Bikaner): The progress of the Rajasthan canal work and the speeding up of its construction following the famine should be discussed in the House. I believe the Government has announced recently that the work on this project is to be slowed down for want of funds. I want this matter to be discussed.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में भी यह सवाल उठा था और आप भी जानते हैं कि बहुत पहले से एक बिल इस सदन के सामने विचाराधीन है—वह बिल पटना के खुदाबख्श ओरियन्टल लाईब्रेरी के बारे में है। पिछले अधिवेशन में कहा गया था कि अगले अधिवेशन में उस पर विचार होगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसके बारे में सरकार ने क्या तय किया है।

दूसरी बात यह है कि इस समय बिहार में प्रेसीडेन्ट रूल है। वहां पर दो लाख 36 हजार सरकारी कर्मचारी काम करते हैं जो अराजपत्रित हैं। उन्होंने दो बार हड़ताल की थी। उनको पांच दिनों की तनख्वाह देने के बारे में, वहां पर जो श्री भोला शास्त्री का मंत्रिमंडल था उसने फैसला किया था कि वह दे देना चाहिए लेकिन वह अभी तक नहीं दिया गया है। पालियामेन्ट के 50 मेम्बरों ने, जितने बड़े-बड़े नेता लोग भी शामिल हैं, उन लोगों ने भी गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि उसको दे देना चाहिए। साथ ही वहां पर कुटीर उद्योग में काम करने वाले लोग पिछले मई के महीने से भूख हड़ताल कर रहे हैं, गवर्नर के सामने

धरना भी दे रहे हैं, वे बेकार बना दिए गए हैं—उसके सिलसिले में भी किसी न किसी प्रकार की चर्चा होनी चाहिए ताकि वहां के सरकारी कर्मचारियों में जो असंतोष है उसका निराकरण हो सके और राजकाज ठीक से चल सके।

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : Sir, one minute.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Seven minutes have gone. What I would suggest is, all these matters could be brought up before the Business Advisory Committee. If you address a communication, I will place it before the Business Advisory Committee and try to find out. (*Interruption*) Shri Shiva Chandra Jha.

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah) : The Time is over; we have to adjourn for lunch.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर सरकार अपना स्टेटमेंट दे। श्री मधु लिमये जी ने जो कहा है वह ठीक कहा है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि एल-सल्वडोर और होंडुरास की जो लड़ाई चल रही है उसमें अमरीका की साजिश है—निक्सन साहब यहां पर आये तो हम जानना चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री ने उसके मुताल्लिक उनसे कुछ बातें की हैं या नहीं? अगर की हैं तो वे बातें क्या हैं?

दूसरी बात यह है कि जेनिवा डिसार्मामेंट कांफ्रेन्स में एशिया के मुल्कों को बुलाया गया है—यूगोस्लाविया को भी इन्वाइट किया है—यूगोस्लाविया न्यूट्रल समिट का मेम्बर है, हिन्दुस्तान, यूगोस्लाविया और अरब तीनों हैं तो जब यूगोस्लाविया को इन्वाइट किया गया है, हिन्दुस्तान को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया है? इसके बारे में भी सरकार स्टेटमेन्ट दे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not the Question Hour. We have already spent nine minutes. Many matters are raised now. The Nixon matter was raised by an hon. lady Member from this side of the House. I would suggest to the Minister concerned one thing. From next time onwards, you just circulate what is going to be taken up in the next week, and if there are suggestions, we shall put them up before the Business Advisory Committee; not on the floor of the House, because there is no limit to it. It is impossible to deal with these matters like this. Now, Dr. Melkote.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Sir, have you not seen me rising? (*Interruption*).

DR. MELKOTE (Hyderabad): Sir, I support the motion made by Shri Bakar Ali Mirza.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I know what you are going to say—it is regarding Telengana. Has the Minister got anything to say?

SHRI RAGHU RAMAIAH: Nothing

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing. Now, there is one point. Yesterday, I asked the Law Minister to circulate, to give the full reply to the communication or the point raised under rule 377 plus the opinion by the Attorney-General. Snri Dandeker suggested that some time should be given for discussion of that matter. So, we will consider it, and then—

STATEMENT *RE.* MATTER UNDER RULE 377

RESIGNATION BY VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT

श्री मधु लिमये (मुंगेर): उसी के बारे में मेरा निवेदन है। आप इनको टेबिल पर रखने के लिए कह रहे हैं, मुझे एतराज़ है। इसमें बहुत गम्भीर कौंस्टीट्युशनल इम्प्रोप्रायटी हो गई है।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under rule 377, a point was raised, and the Minister has made a statement. He cannot raise it now. Two important constitutional issues are involved. Therefore, Shri Dandeker suggested yesterday and you have supported him, if I remember aright, that we should have some sort of debate. We shall consider it in the Business Advisory Committee.